यूपीनेडा को एसएएफ नीति लागू करने की मिलेगी जिम्मेदारी

- कृषि अवशेषों से बनाया जाएगा सतत विमानन ईंधन
- किसानों के क्लस्टर बना कृषि अवशेषों को क्रय किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: राज्य में सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) नीति लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) को सौंपी जाएगी। इस नीति के तहत विमानों के लिए ग्रीन ईंधन का निर्माण करने के लिए संबंधित उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। माना जा रहा है कि एसएएफ नीति को अगले वर्ष तक लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इन्वेस्ट यूपी ने इसे लेकर सतत विमानन ईंधन तैयार करने वाली कंपनियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 16 घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जेवर में बनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवंबर में कर सकते हैं। इसके बाद राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या पांच हो जाएगी। वहीं सात और हवाई अड्डे अगले वर्ष तक तैयार होने की उम्मीद है। इन सभी हवाई अड्डों के तैयार होने के बाद राज्य में विमानन उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सतत विमानन ईंधन तैयार करने की नीति पर काम शुरू किया है। नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

इस नीति के तहत राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेषों, गन्ने की बगास, गेंहू का भूसा, धान की भूसी और इस्तेमाल किए जा चुके तेल से सतत विमानन ईंधन तैयार किया जाएगा। कृषि अवशेषों की आपूर्ति के लिए किसानों के क्लस्टर बनाकर कृषि अवशेषों को क्रय किया जाएगा। इससे किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा। ईंधन तैयार करने के लिए राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का आंकड़े यूपीनेडा ने तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे विशेषज्ञों की मदद से नीति लागू करने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।